

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 81

पेयजल आपूर्ति विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़	3300.00	1.39	3301.39	3300.00	1.39	3301.39	4750.00	1.42	4751.42

	3300.00	1.39	3301.39	3300.00	1.39	3301.39	4750.00	1.42	4751.42
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	3451	...	1.32	1.32	...	1.32	1.32	...	1.35
2. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	3601	1209.75	...	1209.75	1409.74	...	1409.74	2259.75	...
	3602	0.25	...	0.25	0.26	...	0.26	0.35	...
	2215	1400.00	0.07	1400.07	1200.00	0.07	1200.07	1384.90	0.07
	जोड़	2610.00	0.07	2610.07	2610.00	0.07	2610.07	3645.00	0.07
3. ग्रामीण सफाई जोड़-ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	2215	360.00	...	360.00	360.00	...	360.00	630.00	...
		2970.00	0.07	2970.07	2970.00	0.07	2970.07	4275.00	0.07
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	330.00	...	330.00	330.00	...	330.00	475.00	...
कुल जोड़		3300.00	1.39	3301.39	3300.00	1.39	3301.39	4750.00	1.42
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.
1. जलापूर्ति और सफाई	22215	2970.00	...	2970.00	2970.00	...	2970.00	4275.00	...
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	330.00	...	330.00	330.00	...	330.00	475.00	...
जोड़		3300.00	...	3300.00	3300.00	...	3300.00	4750.00	...

1. इसमें पेयजल आपूर्ति विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश की सभी ग्रामीण बसावटों के लिए पेयजल का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ सरकार कुछ वर्षों से ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए वार्षिक केंद्रीय परिव्यय को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है। दसवीं योजना के उद्देश्य में सभी ग्रामीण बसावटों (ऐसी बसावटें शामिल हैं जो पूर्णतः कवर से फिर आंशिक कवर/ कवर न की गई-श्रेणी में आ गई हैं) तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने की व्यवस्था की गई है। व्यापक कार्य योजना, 1999 तथा बाद में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई गई कवरेज स्थिति के संदर्भ में अब 95% से भी अधिक बसावटें पेयजल आपूर्ति से पूर्णतः कवर हैं।

जल गुणवत्ता के स्थायित्व तथा निगरानी को बढ़ावा देने के प्रयासों से

स्थायित्व और गुणवत्ता के दोनों मुद्दों पर समाधान किया जा रहा है। इसके बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों को वर्षा जल एकत्रीकरण के विभिन्न मॉडलों को दर्शाने वाले विवरण दिये गये हैं। समुदाय आधारित जल गुणवत्ता निगरानी और जांच प्रणालियों को संस्थागत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से बनाया गया है।

3. सरकार ग्रामीण लोगों को सफाई सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों को अत्यधिक प्राथमिकता देती रही है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान 452 जिलों में शुरू किया गया है। दसवीं योजना के अंत तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ सभी जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है।

4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं में एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है।